पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की आपराधिक अपील (धारा) 1

में

2019 की आपराधिक पुनरीक्षण सं 383

थाना कांड सं- 85 वर्ष- 2006 थाना- भागलपुर शिकायत मामला जिला-भागलपुर

==========

श्रीमती सुमन देवी, पति- श्री नंदन किशोर झा, और पिता- सच्चिदा नंद झा, उम्र लगभग 46 वर्ष, वर्तमान में निवासी ग्राम एवं डाकघर- भवानीपुर, थाना- गोपालपुर, जिला- भागलपुर।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. महेंद्र झा, पिता- स्वर्गीय शुभंकर झा, निवासी- ग्राम- काझी, थाना- बनमनखी, जिला- पूर्णिया।
3. नंदन किशोर झा, पिता- महेंद्र झा, दोनों निवासी- गांव- काझी, थाना- बनमनखी, जिला- पूर्णिया।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए:	श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए:	श्री अभय कुमार, एपीपी
ओपी संख्या 2 और 3 के लिए:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
	श्री सरोज कुमार, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 323, 498ए और 406*
- *दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4*

संदर्भित मामले:

- *मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752*
- *जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी, (2022) 13 एससीसी 115*
- *रेणु मिश्रा बनाम झारखंड राज्य और अन्य (झारखंड उच्च न्यायालय आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 520/2019 दिनांक 18.04.2024 को तय)*

पुनरीक्षण याचिका *– विवादित निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया, जिसके द्वारा अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि (सजा) के निर्णय को रद्द कर दिया गया।*

प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय में विचारणीय नहीं है।

निर्णय *– याचिकाकर्ता की यह दलील कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई आपराधिक अपील नहीं की जा सकती, असंगत है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आपराधिक अपील का उपाय विधिक प्रावधानों से उत्पन्न होता है, और जब तक दंड प्रक्रिया संहिता अथवा समय-समय पर लागू किसी अन्य विधि में इसका प्रावधान नहीं किया गया हो, कोई अपील विचारणीय नहीं होती। (पैरा 22)*

आपराधिक अपीलों में पारित निर्णयों और आदेशों की सामान्यतः अंतिमता होती है। किंतु, धारा 393 दं.प्र.सं कुछ अपवादों का प्रावधान करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धारा 393 को धारा 377, 378 एवं 384 दं.प्र.सं के प्रावधानों के अधीन माना गया है, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट में अपीलीय निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। धारा 372

दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत भी कहीं यह नहीं कहा गया है कि ऐसी अपील केवल ट्रायल कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है। (पैरा 22)

धारा 401(4) दं.प्र.सं के अनुसार, जहाँ आपराधिक अपील का प्रावधान है और अपील दायर नहीं की गई है, वहाँ वह पक्ष जो अपील कर सकता था, उसकी ओर से पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं होती। हालाँकि, धारा 401(5) दं.प्र.सं हाई कोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित कर उसके अनुसार विचार करे। (पैरा 23)

याचिकाकर्ता को दं.प्र.सं की धारा 372 के प्रावधान के तहत बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के इस न्यायालय में आपराधिक अपील दायर करने का उपाय प्राप्त था। तथापि, याचिकाकर्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। परन्तु, चूँकि याचिकाकर्ता के पास आपराधिक अपील का उपाय उपलब्ध था, अतः वर्तमान पुनरीक्षण याचिका धारा 401(4) दं.प्र.सं के अंतर्गत बाधित होती है। तथापि, धारा 401(5) दं.प्र.सं की उपधारा इस न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह इस पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित कर दे और उस पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय करे। (पैरा 29)

अतः यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका आपराधिक अपील में परिवर्तित की जाती है। (पैरा 30)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार

सीएवी निर्णय

दिनांक: 04-04-2025

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, नौगछिया द्वारा आपराधिक अपील संख्या 77/2014 में दिनांक 07.12.2016 को पारित विवादित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एस.डी.जे.एम., नौगछिया द्वारा दिनांक 06.06.2014 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की गई थी, जिसके द्वारा ओ.पी. संख्या 2/महेन्द्र झा एवं ओ.पी. संख्या 3/नन्दन किशोर झा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 498ए एवं 406 सहपठित धारा 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया था तथा तदनुसार दण्डादेश दिया गया था।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. इस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि पीड़िता सुमन देवी पत्नी नंदन किशोर झा ने चार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत वाद संख्या 85/2006 दर्ज कराई थी, जिसमें ओ.पी. संख्या 2 और 3 शामिल हैं। आपराधिक शिकायत में संज्ञान के बाद चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 323, 498ए और 406 तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप तय किया गया था, जिसमें ओ.पी. संख्या 2/महेंद्र झा और ओ.पी. संख्या 3/नंदन किशोर झा शामिल हैं।

3. विचारण के पश्चात, ओ.पी. संख्या 2 एवं 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 323, 498 ए एवं 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत दोषी पाया गया तथा विद्वान एस.डी.जे.एम. द्वारा तदनुसार सजा सुनाई गई, जबकि शेष दो अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

4. दोषसिद्धि के निर्णय एवं सजा के आदेश से व्यथित होकर, महेंद्र झा/ओ.पी. संख्या 2 एवं नंदन किशोर झा/ओ.पी. संख्या 3 ने सत्र न्यायालय, भागलपुर के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 77/2014 प्रस्तुत की तथा उनकी दोषसिद्धि को खारिज करते हुए आपराधिक अपील स्वीकार कर ली गई।

5. निम्न विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के इस निर्णय से व्यथित होकर, शिकायतकर्ता/सुमन देवी ने प्रारंभ में दिनांक 09.02.2017 को इस न्यायालय के समक्ष एस.एल.ए. संख्या 11/2017 प्रस्तुत किया तथा दिनांक 02.11.2017 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को दोषमुक्ति के विरुद्ध आपराधिक अपील दायर करने की विशेष अनुमति प्रदान की गई। तत्पश्चात, आपराधिक अपील (यू/एस) संख्या 01/2018 दायर की गई। हालांकि, इस आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने उक्त आपराधिक अपील को आपराधिक पुनरीक्षण में परिवर्तित करने की प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना को दिनांक 20.02.2019 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया तथा तदनुसार, आपराधिक अपील (यू/एस) संख्या 1/2018 को वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 383/2019 में परिवर्तित कर दिया गया।

<u>पक्षों की दलीलें</u>

6. हालांकि, पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान, राज्य के विद्वान एपीपी और ओ.पी. संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है।

7. वे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 372 और धारा 378(4) दं.प्र.सं के प्रावधान के मद्देनजर, पीड़ित/याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 09.02.2017 को एसएलए संख्या 11/2017 सही ढंग से दायर किया था और इसे 02.11.2017 के आदेश द्वारा सही ढंग से अनुमति दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को आपराधिक अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी और परिणामस्वरूप, सीआर अपील (यू/एस) संख्या 1/2018 दायर की गई थी। हालाँकि, उक्त आपराधिक अपील को गलत तरीके से वर्तमान आपराधिक संशोधन में परिवर्तित कर दिया गया है। धारा 401 दं.प्र.सं में प्रावधान है कि जब कोई अपील होती है और कोई अपील नहीं की जाती है, तो उस पक्ष द्वारा दायर आपराधिक संशोधन जो अपील कर सकता था, बनाए रखने योग्य नहीं है।

8. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि आपराधिक अपील संख्या 77/2014 में निचली अपीलीय अदालत द्वारा ओ.पी. संख्या 2/महेंद्र झा और ओ.पी. संख्या 3/नंदन किशोर झा को बरी किए जाने के मद्देनजर, याचिकाकर्ता/ शिकायतकर्ता/ पीड़िता ने अपनी पहले से दायर आपराधिक अपील संख्या 77/2014 को वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में परिवर्तित करवाने का सही फैसला किया है, क्योंकि निचली अपीलीय अदालत द्वारा विवादित निर्णय पहले ही पारित किया जा चुका है और अपीलीय निर्णय के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जा सकती। ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ित/याचिकाकर्ता के पास एकमात्र उपाय विवादित निर्णय के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण दायर करना था।

विचारणीय बिंदु

9. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

प्रश्न में शामिल है

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रश्न यह है कि बरी करने के अपीलीय निर्णय के विरुद्ध पीड़ित/याचिकाकर्ता के लिए कानूनी उपाय क्या है - क्या पीड़ित/याचिकाकर्ता ने एसएलए संख्या 11/2017 सही ढंग से दायर किया था और उसके बाद, एसएलए पर आपराधिक अपील (यू/एस) संख्या 1/2018 को अनुमति दी गई थी या उक्त आपराधिक अपील को वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में सही ढंग से परिवर्तित किया गया है।

कानूनी प्रावधान

11. दोषमुक्ति के मामले में आपराधिक अपील धारा 378 दं.प्र.सं के तहत प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है:

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 378

दोषमुक्ति के मामले में अपील। -

[(1) उप-धारा (2) में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, तथा उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन,-

(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है;

(ख) राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश [जो खंड (क) के तहत आदेश नहीं है] या किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित दोषमुक्ति का आदेश।]

(2) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें अपराध की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना या इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा की गई है, तो केंद्रीय सरकार उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लोक अभियोजक को यह भी निर्देश दे सकती है कि वह अपील प्रस्तुत करे-

(क) सत्र न्यायालय में, किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से;

(ख) <u>उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय में [जो खंड (क) के अधीन</u>

आदेश या पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश नहीं है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी।

(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश किसी मामले में पारित किया जाता है जो शिकायत पर शुरू किया गया है और उच्च न्यायालय, शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष अनुमति देता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(5) दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई भी आवेदन, उच्च न्यायालय द्वारा छह माह की अवधि के पश्चात, जहां शिकायतकर्ता लोक सेवक है, स्वीकार नहीं किया जाएगा, तथा अन्य सभी मामलों में दोषमुक्ति के आदेश की तिथि से साठ दिन की अवधि के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) यदि किसी मामले में, दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए उप-धारा (4) के तहत विशेष अनुमति देने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दोषमुक्ति के उस आदेश से उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कोई अपील नहीं की जाएगी। "

(जोर दिया गया)

12. उप-धारा (1), (2) और (3) पुलिस मामले में दोषमुक्ति के मामले में अपील से निपटती हैं, जबकि उप-धारा (4) शिकायत पर शुरू किए गए किसी भी मामले में दोषमुक्ति के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। उप-धारा (5) धारा 378 के तहत ऐसी अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि प्रदान करती है, जबकि उप-धारा (6) यह प्रावधान करती है कि

यदि उप-धारा (4) के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। धारा 378 (1) और 378 (2) के तहत, उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। जब तक कि उच्च न्यायालय की अनुमति न हो। फिर से, धारा 378(4) दं.प्र.सं के तहत अपील, शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति के अनुदान के साथ ही उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

13. धारा 372 दं.प्र.सं में प्रावधान है कि इस न्यायालय या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, आपराधिक न्यायालय के किसी भी फैसले या आदेश से कोई अपील नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक अपील दायर नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में प्रावधान हो। यह भी बताना उचित है कि वर्ष 2009 में धारा 372 दं.प्र.सं में प्रावधान जोड़े जाने से पहले, पीड़ित को कोई भी आपराधिक अपील दायर करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था, सिवाय धारा 378(4) दं.प्र.सं के, जो शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति का अधिकार प्रदान करता है।

14. हालांकि, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान में अपराध के पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें अभियुक्त को बरी किया गया हो या कमतर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया हो और ऐसी अपील उस न्यायालय में की जा सकती है, जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ आमतौर पर अपील की जाती है।

15. धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत पीड़ित द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया के बारे में मतभेद था। एक दृष्टिकोण के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण नहीं है। पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार, धारा 372

दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत भी उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण नहीं है और पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय से अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता है।

16. हालाँकि, **मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय द्वारा विवाद सुलझ गया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण है और पीड़ित को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए किसी अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

17. मल्लिकार्जुन कोडागली मामले (सुप्रा) में, हमले की पीड़िता ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके कारण आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा किए गए अनुवर्ती परीक्षण में, आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इसके बाद, पीड़िता ने बरी किए जाने के खिलाफ धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत 06.02.2009 को उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की। लेकिन अपील को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि धारा 372 का प्रावधान 31.12.2009 से प्रभावी हुआ और घटना उस तारीख से काफी पहले हुई थी। इसके बाद, पीड़िता ने धारा 378(4) दं.प्र.सं के तहत उच्च न्यायालय में एक और आपराधिक अपील दायर की। हालांकि, इस अपील को भी बनाए रखने योग्य नहीं माना गया, जिसमें कहा गया कि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत पर शुरू नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, पीड़िता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मल्लिकार्जुन कोडागली मामले** (सुप्रा) में धारा 372 और धारा 378 दं.प्र.सं पर विस्तार से चर्चा की और पीड़िता की अपील को स्वीकार कर लिया, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया और मामले को उच्च न्यायालय को

भेज दिया ताकि निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई और फैसला किया जा सके। पीड़िता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई अपील दं.प्र.सं की धारा 372 के प्रावधान के तहत सुनवाई योग्य थी। चर्चा के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

> "73. हमारी राय में, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान को भी एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और अपराध के पीड़ित के लिए लाभकारी हो। इसके लिए एक ऐतिहासिक कारण है, जिसकी शुरुआत 29-11-1985 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा 96वें पूर्ण अधिवेशन में अपनाए गए अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा से होती है।
>
> .....
>
> 74. घोषणा को व्यवहार में लाने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध के पीड़ित को कई तरह के अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय कानून में दिए गए औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय और निवारण के तंत्र तक पहुँच में, ऐसे मामले में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल होना चाहिए, जैसा कि हम वर्तमान में चिंतित हैं। इस प्रकाश में विचार किया जाए तो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान को अपराध के पीड़ित को लाभ पहुंचाने के लिए जीवन दिया जाना चाहिए।
>
> 75. परिस्थितियों में, कानून की स्पष्ट भाषा के आधार पर और कई उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के संकल्प के आधार पर, यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 2 (डब्ल्यूए) दं.प्र.सं में परिभाषित एक पीड़ित उस न्यायालय के समक्ष अपील

दायर करने का हकदार होगा, जिसमें सजा के आदेश के खिलाफ आम तौर पर अपील की जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोडागली द्वारा दायर अपील बनाए रखने योग्य थी और इस पर अपने गुणों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

76. जहां तक विशेष अनुमति देने का सवाल है, एक बार फिर, हमें बार में किए गए सबमिशन से अभिभूत होने की जरूरत नहीं है। धारा 372 दं.प्र.सं की शर्त की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, खासकर जब इसकी तुलना धारा 378(4) दं.प्र.सं की भाषा से की जाती है। इस प्रावधान का पाठ बिल्कुल स्पष्ट है और यह शिकायत पर शुरू किए गए मामले में पारित बरी करने के आदेश तक ही सीमित है। "शिकायत" शब्द को धारा 2(डी) दं.प्र.सं में परिभाषित किया गया है और यह मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किए गए किसी भी आरोप को संदर्भित करता है। इसका एफआईआर दर्ज करने या पंजीकरण से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए धारा 372 दं.प्र.सं की शर्त के संबंध में पीड़ित के शिकायतकर्ता होने के प्रभाव पर विचार करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

अंतिम आदेश

77. ऊपर वर्णित कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है और मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम के निर्णय और आदेश। कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि वह कोडागली द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करे और निर्णय ले सके, जो बागलकोट (कर्नाटक) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 28-10-2013 को पारित बरी करने के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। "

(जोर दिया गया)

19. हालांकि, **मल्लिकार्जुन कोडगली मामले** (सुप्रा) में अल्पमत के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत अपील दायर करने के पीड़ित के अधिकार को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे दं.प्र.सं की धारा 378(3) और धारा 378(4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति या विशेष अनुमति देने का प्रावधान करता है। पीड़ित के अधिकार को आरोपी के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, तो आरोपी की निर्दोषता की धारणा मजबूत हो जाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले पर गौर करना चाहिए और पहले यह तय करना चाहिए कि अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीड़ित द्वारा दायर अपील में ऐसी जांच न की जाए। पीड़ित को राज्य या शिकायत से ऊपर नहीं रखा जा सकता है।

20. जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी, (2022) 13 एससीसी 115 इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का एक और ऐतिहासिक फैसला है, जो **मल्लिकार्जुन कोडगली** मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा दिया गया है। इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 324 और 326 के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। दोषियों ने सत्र न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील की और पीड़िता ने धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी करने के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय के समक्ष अपील की। एक सामान्य निर्णय द्वारा, अभियुक्तों की अपील को अनुमति दी गई, जबकि पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर, पीड़ित ने धारा 397 सहपठित धारा 401 दं.प्र.सं के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को

प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने धारा 401 दं.प्र.सं के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को बहाल कर दिया। चर्चा के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

> "8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, इस न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:
>
> 8.1. (i) क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 401 दं.प्र.सं के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करना तथा दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करके अभियुक्त को दोषी ठहराना न्यायोचित है?
>
> 8.2. (ii) ऐसे मामले में जहां पीड़ित को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है, जैसा कि अब धारा 372 दं.प्र.सं के अंतर्गत प्रदान किया गया है तथा पीड़ित ने ऐसा कोई उपाय नहीं अपनाया है तथा अपील नहीं की है, क्या अपील करने के बजाय पक्ष/पीड़ित के कहने पर पुनरीक्षण आवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है?
>
> 8.3. (iii) धारा 401 दं.प्र.सं के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (5) में संशोधन आवेदन को अपील याचिका के रूप में माना गया है और तदनुसार उससे निपटा गया है, तो क्या उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता है?
>
> .....
>
> 13. अब जहां तक मुद्दा (ii) का संबंध है, अर्थात, ऐसे मामले में जहां कोई अपील नहीं की गई है, हालांकि अपील संहिता के तहत आती है, क्या उस

पक्षकार के अनुरोध पर संशोधन आवेदन पर अभी भी विचार किया जाना है, जो अपील कर सकता था, इसका उत्तर धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (4) में ही निहित है। धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (4) इस प्रकार है:

"401. (4) जहां इस संहिता के तहत अपील की जाती है और कोई अपील नहीं की जाती है, उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता था।

13.1. यह विवादित नहीं हो सकता है कि अब धारा 372 दं.प्र.सं में 2009 के बाद संशोधन और धारा 372 दं.प्र.सं में प्रावधान डालने के बाद, पीड़ित को बरी के आदेश के खिलाफ अपील करने का वैधानिक अधिकार है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां कोई अपील पेश नहीं की जाती है और पीड़ित को अपील दायर करने के लिए भेजा जाना है, बरी के आदेश के खिलाफ पीड़ित के कहने पर कोई पुनरीक्षण नहीं माना जाएगा। यहां तक कि यह पीड़ित के स्वयं के हित में होगा क्योंकि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, दायरा बहुत सीमित होगा, हालांकि, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय क्षेत्राधिकार के तहत, अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार होगा। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां शिकायत पर शुरू किए गए किसी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है, **शिकायतकर्ता (पीड़ित के अलावा)** धारा 378 दं.प्र.सं की उपधारा (4) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति दी जाए।

13.2. जैसा कि इस न्यायालय ने मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752 में देखा, जहां तक पीड़ित का संबंध है, पीड़ित को अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने की

आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीड़ित को धारा 372 प्रावधान के तहत अपील करने का वैधानिक अधिकार है और धारा 372 का प्रावधान शिकायतकर्ता के मामले में धारा 378 दं.प्र.सं की उपधारा (4) की तरह अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करता है और ऐसे मामले में जहां शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है। बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का पीड़ित को प्रदान किया गया अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। इसलिए, जहां तक मुद्दा (ii) का संबंध है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां पीड़ित और/या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, ने धारा 372 दं.प्र.सं या धारा 378(4) के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील का उपाय नहीं किया है और/या उसका लाभ नहीं उठाया है, जैसा भी मामला हो, पुनरीक्षण आवेदन, पीड़ित या शिकायतकर्ता के कहने पर बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ़ कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और पीड़ित या शिकायतकर्ता को धारा 372 या धारा 378(4) के तहत अपील करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसलिए मुद्दा (ii) का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। "

(जोर दिया गया)

21. इसलिए, **जोसेफ स्टीफन केस** (सुप्रा) और **मल्लिकार्जुन कोडागली केस** (सुप्रा) के बाद, यह तय हो गया है कि धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत अपील करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण है। पीड़ित को धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय से अपील दायर करने के लिए कोई अनुमति या विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, शिकायत मामले में, शिकायतकर्ता, जो पीड़ित नहीं है, को उच्च न्यायालय से धारा 378(4) दं.प्र.सं के तहत आवश्यक विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि वह उसके समक्ष अपील दायर कर सके। **जोसेफ स्टीफन केस** (सुप्रा) के पैरा 13.1 की अंतिम

पंक्ति से यह स्पष्ट है। इसके अलावा, शिकायत मामले और पुलिस मामले दोनों के पीड़ित समान रूप से धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के अपील दायर करने के हकदार हैं, जैसा कि धारा 378(3) और 378(4) दं.प्र.सं के तहत आवश्यक है, क्योंकि धारा 372 दं.प्र.सं का प्रावधान पुलिस मामले और शिकायत मामले के पीड़ित के बीच भेदभाव नहीं करता है।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस कथन में भी कोई दम नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई आपराधिक अपील नहीं की जा सकती। यहां यह बताना प्रासंगिक हो जाता है कि आपराधिक अपील का उपाय कानून का ही हिस्सा है और जब तक दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में इसका प्रावधान नहीं है, तब तक कोई अपील स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि धारा 372 दं.प्र.सं से स्पष्ट है और यह भी सच है कि धारा 393 दं.प्र.सं के अनुसार आपराधिक अपील में पारित निर्णय और आदेश आम तौर पर अंतिम होते हैं। लेकिन धारा 393 दं.प्र.सं भी सामान्य नियम के कुछ अपवादों के लिए धारा 393 दं.प्र.सं के सामान्य प्रावधान को धारा 377, 378 और 384 दं.प्र.सं के प्रावधानों के अधीन बनाकर प्रावधान करती है, जिसके तहत अपीलीय निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीड़ितों द्वारा केवल ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही अपील दायर की जा सकती है।

23. अब, धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (4) और (5) लागू होती है। धारा 401(4) दं.प्र.सं में प्रावधान है कि जहां आपराधिक अपील होती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहां अपील करने वाले पक्ष के कहने पर कोई आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, धारा 401(5) उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में मानने और उसके अनुसार उससे निपटने में सक्षम बनाती है।

24. धारा 401 दं.प्र.सं उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है जो इस प्रकार है:

"**401. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियाँ** - (1) किसी कार्यवाही के मामले में जिसका रिकॉर्ड स्वयं द्वारा मंगवाया गया है या जो अन्यथा उसके ज्ञान में आता है, उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार धारा 386, 389, 390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकता है और जब पुनरीक्षण न्यायालय के न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित हो, तो मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा प्रदान की गई विधि से किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत कोई भी आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रतिकूल नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने बचाव में अधिवक्ता द्वारा सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।

(3) इस धारा में कोई भी बात उच्च न्यायालय को किसी निष्कर्ष को परिवर्तित करने के लिए अधिकृत नहीं समझी जाएगी। दोषसिद्धि में दोषमुक्ति।

(4) <u>जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहां उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता था</u>।

(5) <u>जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत धारणा के तहत किया गया था कि उस पर कोई अपील नहीं की जा सकती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए</u>

आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मान सकता है और उसके अनुसार उस पर कार्रवाई कर सकता है। "

(जोर दिया गया)

25. यहां, **जोसेफ स्टीफन मामले** (सुप्रा) का संदर्भ देना फिर से लाभदायक होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह धारा 372 दं.प्र.सं के तहत आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में माने और अपने स्वयं के गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार इसका फैसला करे। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में मानने के लिए, उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में बदलने के लिए न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

".....जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार, धारा 401 दं.प्र.सं की उपधारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानते हुए, उच्च न्यायालय को एक न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़ित होने के बावजूद भी उन्हें धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के अनुसार अपील का वैधानिक अधिकार है, हम इस मामले को उच्च न्यायालय को सौंपना उचित समझते हैं ताकि पुनरीक्षण आवेदन को धारा 372 दं.प्र.सं के तहत अपील की याचिका के रूप में माना जा सके और कानून के अनुसार और उनके अपने गुणों के आधार पर उनका फैसला किया जा सके। यह सभी के हित में होगा, अर्थात् पीड़ितों के साथ-साथ अभियुक्तों के भी, क्योंकि अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण न्यायालय की तुलना में अपीलीय न्यायालय के रूप में व्यापक दायरा और अधिकार क्षेत्र होगा। "

(जोर दिया गया)

26. जोसेफ स्टीफन केस (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय ने **रेणु मिश्रा बनाम झारखंड राज्य और अन्य** (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 520/2019, दिनांक 18.04.2024 को निर्णीत) के मामले में बरी किए जाने के अपीलीय निर्णय के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय माना। परसुडीह पी.एस. केस संख्या 309/2012 से उत्पन्न इस मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया था। हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया था। इसलिए, सूचक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने **जोसेफ स्टीफन मामले** (सुप्रा) के फैसले के आलोक में आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय मानते हुए खारिज कर दिया और पीड़ित/याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी।

<u>वर्तमान मामला</u>

27. वर्तमान मामले की बात करें तो, मुझे पता चला है कि पीड़िता, जो इस मामले में याचिकाकर्ता है, की आपराधिक शिकायत पर, चार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत मामला संख्या 85/2006 दर्ज किया गया था, जिसमें विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 शामिल हैं, जिन्हें विद्वान एस.डी.जे.एम. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 498ए और 406 के साथ धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था और तदनुसार सजा सुनाई गई थी। इस दोषसिद्धि और सजा के आदेश को विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें आपराधिक अपील संख्या 77/2014 दायर की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें उनकी दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया था। इसलिए, पीड़िता ने नीचे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय के खिलाफ वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है।

28. प्रारंभ में, पीड़िता ने 09.02.2017 को एसएलए संख्या 11/2017 दायर किया था और एसएलए की अनुमति दिए जाने के बाद, आपराधिक अपील (यू/एस) संख्या 1/2018 दायर की गई थी, लेकिन उक्त आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान, पीड़िता/याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर आपराधिक अपील को वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में परिवर्तित कर दिया गया था।

29. उउपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और बाध्यकारी न्यायिक मिसालों को देखते हुए, पीड़ित-याचिकाकर्ता के पास बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के धारा 372 दं.प्र.सं के प्रावधान के तहत इस न्यायालय में आपराधिक अपील दायर करने का उपाय था। हालांकि, पीड़ित-याचिकाकर्ता ने एसएलए को प्राथमिकता दी थी जिसे अनुमति दी गई थी और बाद में आपराधिक अपील (यू/एस) संख्या 1/2018 दायर की गई थी और इसे गलती से वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन पीड़ित-याचिकाकर्ता के लिए आपराधिक अपील के उपाय की उपलब्धता के मद्देनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण धारा 401(4) दं.प्र.सं द्वारा मारा जाता है। हालांकि, धारा 401 दं.प्र.सं की उप-धारा 5 इस न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने और तदनुसार उसका इलाज करने और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

<u>निष्कर्ष/आदेश</u>

30. इसलिए, इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित किया जाता है। कार्यालय को इस पुनरीक्षण याचिका में आवश्यक सुधार करने और माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अपील को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।